



उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Limited

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division, Ghazipur.
220 KV S/S Talwal Hydle
Colony Ghazipur
Pin 233002

(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Mobile No. 9415311047

E-mail - eeetd2var@upptcl.org

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड, गाजीपुर
220 के०वी० विद्युत् उपकेंद्र तलवल
हाइडिल कालोनी गाजीपुर
पिन 233002

पत्रांक. 1542 वि०प्रे०खं-(गा०)/

दिनांक. 29.06.2022

विषय:- 400 के०वी० अनपरा-वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ द्वारा लगाये गये कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा, सोनभद्र।

संदर्भ:- 1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक
3393/11-सी०FP/UP/TRANS/32650/2018 दिनांक 31.05.2022
2. आपके कार्यालय पत्रांक 3021/ओबरा/15 भू०ह० दिनांक 16.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा 400 के०वी० अनपरा-वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप दण्डात्मक एन०पी०वी० देने हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र से सम्बन्धित कमियां दर्शायी गयी है, जिसके के कम में अवगत कराना है कि 400 के०वी० अनपरा-वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 319.28 हे० वनभूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या- 08-197/91-एफ.सी. दिनांक-01.11.1993 द्वारा गैरवानिकी कार्य हेतु उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) को हस्तान्तरित किया गया था, जिसमें कोई समय सीमा वर्णित नहीं है, अर्थात् भारत सरकार द्वारा उक्त वनभूमि को उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु 20 वर्षों के लिए हस्तान्तरित नहीं किया गया केवल इसके क्रम में संयुक्त सचिव उ.प्र. शासन के आदेश संख्या- जी आई. 444/14-2-93-707/89 दिनांक- 08/23 फरवरी 1994 द्वारा उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु 20 वर्षों के लिए लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी जबकि उक्त अनुमति पत्रों के शर्तों में 20 वर्ष का कोई जिक्र नहीं है। संयुक्त सचिव उ०प्र० शासन के आदेश पत्र के बिन्दु संख्या 03 में उल्लेखित है कि उक्त भूमि उ०प्र०रा०वि०प० (वर्तमान में उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड) के उपयोग में पट्टा अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी जब तक कि उ०प्र०रा०वि०प० (वर्तमान में उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड) उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता बनी रहेगी, इसलिए वर्ष 2014 में लीज समाप्ति के पश्चात तत्काल इस कार्यालय द्वारा उक्त वनभूमि को पुनः लीज पर लेने हेतु लीज नवीनीकरण प्रस्ताव सम्बन्धित वन प्रभाग में जमा कर दिया गया था तथा सम्बन्धित वन प्रभाग से मिलकर लीज नवीनीकरण प्रस्ताव को शीघ्र पूर्ण कराने की कोशिश की गयी। लीज नवीनीकरण प्रक्रिया जटिल होने एवं लीज नवीनीकरण प्रक्रिया की कोई स्पष्ट गाइड लाइन न होने के कारण लीज नवीनीकरण प्रक्रिया में समय लग रहा है, इसलिये उक्त परियोजना के लीज नवीनीकरण प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक विलम्ब हुआ है, जिसमें किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोष नहीं है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि वर्ष 2014 में लीज समाप्ति के पश्चात भी इस कार्यालय द्वारा उक्त वनभूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु उपयोग किये जाने को भारत सरकार की उल्लंघन से सम्बन्धित गाइड लाइन दिनांक 29.01.2018 में उल्लेखित उल्लंघन की श्रेणी में न माना जाये, क्योंकि उक्त गाइड लाइन नये वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति से सम्बन्धित है न कि पूर्व में दिये गये अनुमति से क्योंकि उक्त परियोजना उक्त वनभूमि पर वर्ष 1994 से बनी है जिसे वर्ष 2014 में लीज अवधि समाप्त होने के पश्चात उक्त वनभूमि से हटाया नहीं जा सकता है। उ०प्र०रा०वि०प०(वर्तमान में उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड) को उक्त वनभूमि के उपयोग की आवश्यकता अभी भी है, जिस कारण उक्त वनभूमि को उ०प्र० सरकार से पुनः लीज पर लेने तथा पट्टा कराने हेतु लीज नवीनीकरण प्रस्ताव को सम्बन्धित वन प्रभाग में वर्ष 2014 में जमा कर दिया गया था। वर्ष 2014 के पश्चात उक्त वनभूमि का

[Handwritten signature]

गैरवानिकी कार्य हेतु उपयोग किये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित वनप्रभागों को उनके लीज रेन्ट मॉगपत्र के अनुसार लीज रेन्ट भी वर्ष 2014 से अब तक ससमय जमा किया जाता रहा है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त वनभूमि का पुनः उपयोग करने एवं उ०प्र० सरकार द्वारा पुनः लीज पर लेने तथा नया पट्टा कराने हेतु जमा किये गये लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में दण्डात्मक एन०पी०वी० न लगाये तथा प्रस्ताव को उ०प्र० सरकार को प्रेषित करने की कृपा करें, ताकि उक्त वनभूमि को पुनः लीज पर लिया जा सके। उक्त लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में पुनः उक्त वनभूमि का गैरवानिकी प्रयोग हेतु भारत सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उक्त वनभूमि का गैरवानिकी प्रयोग हेतु पूर्व में ही भारत सरकार के पत्र संख्या- 08-197/91-एफ.सी. दिनांक-01.11.1993 द्वारा उक्त वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग करने हेतु अनुमति उ०प्र०रा०वि०प०(वर्तमान में उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड) को प्राप्त है।

(एस०के०सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक.

वि०प्र०खं०-(गा)/

दिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ ।
2. मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग रेनूकुट / सोनभद्र / मिर्जापुर / कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर ।
4. मुख्य अभियन्ता, (पा०उ०पू०) उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, गोरखपुर ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, गाजीपुर ।

1
(एस०के०सिंह)

अधिशासी अभियन्ता